



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 363]

नई दिल्ली, शनिवार, प्रवृत्त 27, 1973/कार्तिक 5, 1895

No. 363]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 27, 1973/KARTIKA 5, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह प्रलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October 1973

S.O. 665(E).—The following Order made by the President is published for general information,

ORDER

Whereas by a Proclamation issued on the 18th January, 1973 under clause (1) of article 356 of the Constitution of India it has been declared that the powers of the Legislature of the State of Andhra Pradesh shall be exercisable by or under the authority of Parliament;

And whereas Parliament has authorised expenditure from the Consolidated Fund of that State for the services of the financial year 1973-74;

And whereas the amount so authorised is found to be insufficient in cases of certain services and also a need has arisen in certain cases for meeting additional expenditure not contemplated in the Annual Financial Statement of that year;

And whereas the House of the People is not in session and it is necessary to authorise expenditure from the Consolidated Fund of the State pending the sanction of such expenditure by Parliament;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (c) of clause (1) of article 357 of the Constitution, I. V. V. Giri, President of India, hereby authorise that, pending the sanction by Parliament, expenditure of sums not exceeding those specified in column 3 of the Schedule annexed hereto and amounting in the

aggregate to the sum of fourteen crores, sixty-two lakhs and forty-three thousand rupees may be incurred from and out of the Consolidated Fund of the State of Andhra Pradesh towards defraying the several charges during the financial year 1973-74 in respect of the services and purposes specified in column 2 of the said Schedule.

THE SCHEDULE

Serial No.	Demand No. and services and purposes	Sums not exceeding		
		Expenditure charged on the Consolidated Fund of the State of Andhra Pradesh	Other Expenditure to be met out of the Consolidated Fund of the State of Andhra Pradesh	Total
1	2	3	4	5
		Rs.	Rs.	Rs.
1	IX—Heads of State, Ministers and Head-quarters Staff	6,45,000	6,45,000
2	XVII—Education	57,000	2,20,88,000	2,21,45,000
3	XIX—Public Health and Family Planning	18,55,000	18,55,000
4	XX—Agriculture	1,41,05,000	1,41,05,000
5	XXI—Fisheries	90,000	90,000
6	XXII—Animal Husbandry	1,80,000	..	1,80,000
7	XXIII—Co-operation	2,000	..	2,000
8	XXIV—Industries	24,67,000	24,67,000
9	XXV—Community Development Project, National Extension Service and Local Development Works	10,80,000	10,80,000
10	XXVII—Other Miscellaneous, Social and Developmental Organisations	4,00,09,000	4,00,09,000
11	XXIX—Welfare of Scheduled Tribes, Castes and Other Backward Classes	41,22,000	41,22,000
12	XXXII—Electricity	11,90,000	11,90,000
13	XXXIII—Public Works	17,32,000	17,32,000
14	XXXV—Famine Relief	10,00,000	10,00,000
15	XL—Forest Department	11,42,000	11,42,000
16	XLI—Miscellaneous	3,57,000	3,57,000
17	XLII—Municipal Administration	18,66,000	18,66,000
18	XLVII—Capital Outlay on Industrial and Economic Development	65,36,000	1,97,91,000	2,63,27,000
19	LI—Capital Outlay on Public Works	2,48,000	67,83,000	70,31,000
20	LVI—Loans and Advances by the State Government	1,88,98,000	1,88,98,000
		70,23,000	13,92,20,000	14,62,43,000

V. V. GIRI,
President.

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर, 1973

का० आ० 665 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया निम्नलिखित आदेश सामान्य सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

आदेश

चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 की धारा (1) के अधीन 18 जनवरी, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा द्वारा घोषित किया गया है कि आंध्र प्रदेश राज्य के विधान-मण्डल के अधिकारों का प्रयोग संसद् द्वारा अथवा इसके प्राधिकार के अधीन किया जायगा ;

और चूंकि संसद ने वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए उस राज्य की समेकित निधि से व्यय किये जाने की स्वीकृति दी है ;

और चूंकि इस प्रकार स्वीकृत रकम कुछ सेवाओं के सम्बन्ध में अपर्याप्त सिद्ध हुई है और अनिश्चित व्यय को पूरा करने की भी आवश्यकता पैदा हो गयी है जिसकी परिकल्पना उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में नहीं की गयी थी ;

और चूंकि लोक सभा का मत नहीं चल रहा है और जब तक संसद से ऐसे व्यय की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक राज्य की समेकित निधि से व्यय का प्राधिकार दिया जाना आवश्यक है ;

अब, इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 357 की धारा (1) की उप-धारा (ग) के अनुसार, मैं, ब्राह्मगिरि ब्रैकटगिरि, भारत का राष्ट्रपति एतद्द्वारा, संसद् की स्वीकृति प्राप्त होने तक, संलग्न अनुसूची के कालम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में 1973-74 के वित्तीय वर्ष में विभिन्न खर्चों को पूरा करने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य की समेकित निधि में से उक्त अनुसूची के कालम 3 में निर्दिष्ट रकमों से अतिरिक्त और बीस करोड़ बासठ लाख तैंतीस हजार रुपये की कुल रकम का व्यय करने की स्वीकृति देता हूँ ।

अनुसूची

निम्नलिखित राशियों से अनधिक				
संख्या और तथा प्रयोजन	आन्ध्र प्रदेश राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय	आन्ध्र प्रदेश राज्य की समेकित निधि से किया जाने वाला अन्य व्यय	जोड़	
1	2	3	4	5
	रुपये	रुपये	रुपये	
1. IX — राज्यों के प्रमुख, मंत्रिगण और मुख्यालय कर्मचारी वर्ग .		6,45,000	6,45,000	
2. XVII — शिक्षा .	57,000	2,20,88,000	2,21,45,000	
3. XIX — लोक-स्वास्थ्य और परिवार नियोजन.	—	18,55,000	18,55,000	
4. XX — कृषि .	—	1,41,05,000	1,41,05,000	
5. XXI — मत्स्य-पालन .	—	90,000	90,000	
6. XXII — पशु-पालन .	1,80,000	—	1,80,000	
7. XXIII — सहकारिता .	2,000	—	2,000	
8. XXIV — उद्योग .	—	24,67,000	24,67,000	
9. XXV — सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास कार्य	—	10,80,000	10,80,000	
10. XXVII — अन्य विविध सामा- जिक तथा विकास संबंधी संगठन	—	4,00,09,000	4,00,09,000	
11. XXIX — अनुसूचित जन जातियों, वन- जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों का कल्याण	—	41,22,000	41,22,000	

1	2	3	4	5
		रुपये	रुपये	रुपये
12. XXXII— विद्युत .	—	11,90,000	11,90,000	
13. XXXIII—सार्वजनिक निर्माण कार्य .	—	17,32,000	17,32,000	
14. XXXV —दुर्भिक्ष सहायता .	—	10,00,000	10,00,000	
15. XL -- वन विभाग .	—	11,42,000	11,42,000	
16. XLI -- विविध .	—	3,57,000	3,57,000	
17. XLII --नगरपालिका प्रशासन	—	18,66,000	18,66,000	
18. XLVII-- औद्योगिक और ग्राम्य विकास पर पूंजी परिव्यय	65,36,000	1,97,91,000	2,63,27,000	
19. LI -- सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय .	2,48,000	67,83,000	70,31,000	
20. LVI -- राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और ग्राम्य .	—	1,88,98,000	1,88,98,000	
जोड़ :	70,23,000	13,92,20,000	14,62,43,000	

बराहगिरि बैंकटगिरि,
राष्ट्रपति ।

[सं० एक० 3(75)—बी/73]

बी० मैत्रेयन, संयुक्त सचिव ।

